Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

जनवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिये 24.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति 3
- राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की पाँचवी बैठक आयोजित 3
- राष्ट्रपति ने राजस्थान में संविधान उद्यान का किया लोकार्पण 3
- 'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' लागू 4
- राष्ट्रपति ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जंबूरी का किया उद्घाटन 5
- मुख्यमंत्री ने उदयपुर में सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का किया लोकार्पण 5
- मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 5
- पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 6
- सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में राजस्थान देश में अव्वल 7
- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर 7
- रालसा के वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन 8
- अठारहवीं राष्ट्रीय जंबूरी का समापन 8
- बीकानेर हाउस प्रबधंन समिति और भारत कला मेला के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9
- लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम का शुभारंभ 9
- विद्युत उपभोक्ताओं के लिये एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू 10
- अंधता नियंत्रण के लिये पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान 11
- मुख्यमंत्री ने 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के प्रारूप का किया अनुमोदन 11
- मुख्यमंत्री ने 'गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना' को दी सहमति 12
- मुख्यमंत्री ने 'गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना' को दी सहमति 12
- 'हर घर पंचायत अभियान' का शुभारंभ 12
- राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन 13
- राज्यपाल ने 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक का किया लोकार्पण 13
- राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य एमओयू 14
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 'FITUR-2023' में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया 14
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिये राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद और आरोह कंसल्टिंग के बीच करार 15
- राजकीय महाविद्यालयों में हुआ गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन 15
- एमओयू साइनिंग सेरेमनी 16
- मुख्यमंत्री ने दी पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु समिति के गठन की मंजूरी 16
- विधानसभा अध्यक्ष ने बनास नदी पर किया एनिकट का शिलान्यास 17
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने हरमाड़ा में किया शहरी जल संवर्द्धन योजना का शिलान्यास 17
- केंद्रीय कारागार अलवर में 'आशाएँ दा फिलिंग स्टेशन' का शिलान्यास 17
- राजस्थान टूरिज़्म पोलो कप टूर्नामेंट 18
- समूचे प्रदेश में एक माह का खान सुरक्षा अभियान शुरू 18
- अब भिवाड़ी में भी होगी एसीबी चौकी 19
- राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार का द्वीप, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नामकरण 20
- राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल हुई 25 डिजिटल इंटरसेप्टर 20
- कैंपा की संचालन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित 21
- प्रदेश के आठ रचनाधर्मियों को मिलेगा अमृत सम्मान 21
- प्रदेश की चार विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित 22
- भगवान श्री देवनारायण जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित 23
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 23
- पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद की संयुक्त बैठक 24
- प्रदेश में अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क्स की स्थापना हेतु टी.एच.डी.सी.एल. एवं आर.आर.ई.सी.एल. के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता का जे.वी. एग्रीमेंट निष्पादित 24
- पशु कल्याण पखवाड़े के अंतिम दिन सर्वोदय दिवस का हुआ आयोजन 25

नोट :

राजस्थान

प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिये 24.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

31 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में प्रदेश के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिये 24 करोड़ 87 लाख 22 हज़ार रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे आमजन को अपने शहर में ही सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिये घोषणा की गई थी। इसी क्रम में यह स्वीकृति दी गई है।

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की पाँचवी बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में जयपुर में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की पाँचवी बैठक आयोजित हुई, जिसमें आर्द्रभूमि को संरक्षित रखने के लिये अधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा राज्य के 20 ज़िलों में स्थित 50 आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने की अनुमति प्रदान की गई तथा आगामी समय में इनकी संख्या बढाकर 100 से अधिक किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा सांभर क्षेत्र में प्रस्तावित डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक के लिये 04 हैक्टर में कार्य कराने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमति के लिये भेजने का निर्णय भी लिया गया।
- मंत्री हेमराम चौधरी ने बैठक में पर्यावरण विभाग द्वारा की गई 'राज्य पर्यावरण योजना'का विमोचन भी किया, जिसके तहत विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, आर्द्र भूमि प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण, खनन द्वारा प्रदूषण, ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि के संबंध में कार्ययोजना क्रियान्वित की जाएगी।

राष्ट्रपति ने राजस्थान में संविधान उद्यान का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों में संवैधानिक नैतिकता की भावना जाग्रत करने के लिये कार्य किये जाने पर बल देते हुए राजस्थान में जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिये स्थापित पारेषण तंत्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने एक हज़ार मेगावाट की बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास भी किया।
- राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान उद्यान के लोकार्पण के बाद राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राजभवन में इस तरह का संविधान उद्यान बनकर तैयार हुआ है।
- उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसे तैयार किया गया है। गत वर्ष 26 जनवरी को संविधान उद्यान का राजभवन में शिलान्यास हुआ था।
- राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्मित करने की पहल की गई है और राज्य की विधानसभा में अभिभाषण से पूर्व संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाने के साथ मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाने की परंपरा का सूत्रपात किया गया है। इसी क्रम में राजभवन आने वाले सभी सामान्य और विशिष्टजन को संविधान से जुड़ी हमारी आदर्श संस्कृति से प्रत्यक्ष जोड़ने के उद्देश्य से संविधान उद्यान का निर्माण यहाँ किया गया है।
- राज्यपाल ने बताया कि संविधान उद्यान देश के पवित्र संविधान के 22 भागों का ही कला-रूप नहीं है बल्कि यह संविधान से जुड़े आदर्शों और संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। यहाँ भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति बेहद कलात्मक ही नहीं संस्कृति के आदर्श को प्रस्तुत करने वाली है। प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर में मोहन जोदड़ों की सभ्यता के प्रतीक घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चित्रों से सज्जित किया गया है।
- यहाँ महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों के बनाए रेखांकनों को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिष्यों के साथ यज्ञ करते वैदिक ऋषि का आश्रम, नटराज की मूर्ति, महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी कलाकृतियाँ, रेगिस्तान और गांधीजी की डांडी यात्रा, सुभाष बोस की आज़ाद हिन्द फौज, देवी-देवताओं, महात्मा बुद्ध आदि के रेखांकन प्रदर्शित किये गए हैं।

'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' लागू

चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में हुई बैठक में बताया कि 'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' लागू हो गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के तहत हितधारकों द्वारा आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों का सर्वे पूर्ण करवाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि सर्वे के उपरांत आए निष्कर्षों के आधार पर योजना की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। सर्वे का कार्य संभाग स्तर, ज़िला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सर्वे कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये जाने पर हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
- उन्होंने बताया कि बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था के साथ आश्रय उपलब्ध कराना तथा उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये शिक्षा सशक्तीकरण, पर्याप्त रोज़गार सृजन के साथ प्रशिक्षण के अवसर सहित स्वरोज़गार एवं सामाजिक हकों की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि 'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- इसके अलावा नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिये शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा।

नोट :

राष्ट्रपति ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जंबूरी का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

4 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राजस्थान के पाली ज़िले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जंबूरी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जंबूरी में भारत सहित घाना, मलेशिया, सउदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल सहित विभिन्न देशों से आए 37 हज़ार से अधिक स्काउट एवं गाइड्स ने शिरकत की।
- समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बताया कि युवाओं के इस सम्मेलन में नायाब जोश एवं ऊर्जा का समागम है। युवाओं की यह सभा मिनी यंग इंडिया है। स्काउट तन-मन से इंसानियत एवं समाज सेवा का काम करते हैं। यह गर्व की बात है कि पूरे देश में सबसे अधिक संख्या में स्काउट साहस एवं वीरता के प्रतीक राजस्थान की भूमि से हैं।
- उन्होंने बताया कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन द्वारा लगभग 115 वर्षों से युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी सहित अन्य कई लोग इस संगठन के प्रशंसक रहे।
- देश का सबसे बड़ा यह संगठन चरित्र निर्माण के लिये जो कार्य करता है, वह अद्भुत है। इस संगठन में 63 लाख से अधिक स्काउट एवं गाइड हैं।
- समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश में 12 लाख से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स हैं। इन्होनें अनुशासित सिपाही की तरह कार्य कर कोविड प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा जंबूरी स्मारिका, विशेष आवरण तथा जंबूरी पत्रिका का भी विमोचन किया गया। इस दौरान 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने उदयपुर में सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उदयपुर ज़िले को बड़ी सौगात देते हुए शहर के व्यस्ततम मार्ग पर दो सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि उदयपुर में दोनों फ्लाईओवर संचालित होने से आस-पास के क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा तथा शहरवासियों को आने-जाने में सुविधा होगी।
- उल्लेखनीय है कि उदयपुर में 19.55 करोड़ रुपए की लागत से सेवाश्रम फ्लाईओवर तथा 19.86 करोड़ रुपए की लागत से कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उदयपुर ज़िले के गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार खेलों व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये लगातार उच्च स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करवा रही है, जिससे राज्य में आजादी के बाद पहली बार खेलों के लिये सकारात्मक माहौल बना है और एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है।

नोट :

- राज्य सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों के साथ ही सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।
- सरकार द्वारा खेल स्पर्धाओं व प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से चिह्नित प्रतिभाओं को अच्छी सुविधाएँ, कोच व माहौल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पहली बार एक साथ 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 10 लाख महिला खिलाड़ी भी थीं। ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक खेल प्रारंभ हो रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को तलाशने का कार्य किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि इस बार का बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। आने वाले बजट में आदिवासी अंचल के विकास के लिये उचित प्रावधान किये जाएंगे तथा खिलाड़ियों से आह्वान किया गया कि वे प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने खेल कौशल को निरंतर निखारें ताकि प्रत्येक ज़िले से उत्कृष्ट खिलाड़ी उभरकर आगे आएँ।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी स्पोर्टस स्कूल खोलने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बाल्यकाल से ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिल सकेगा।
- इसके अलावा, उन्होंने जनजातीय खिलाड़ियों के लिये एक महीने का विशेष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने की भी घोषणा की।

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव

चर्चा में क्यों ?

6जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 'पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव' का उद्घाटन किया। 'विकासशील राजस्थान-उद्यमशील राजस्थान'की मुख्य थीम पर केंद्रित 33वाँ उत्सव 15 जनवरी तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्सव में केंद्रीय पंडाल, औद्योगिक प्रदर्शनी, विकास प्रदर्शनी, सी-वर्ल्ड, आदिदेव महादेव की प्रतिमा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित उत्पादों व मॉडल्स आदि की जानकारी लेकर लोगों का हौसला बढ़ाया।
- यह आयोजन जोधपुर ज़िला प्रशासन, ज़िला उद्योग केंद्र उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर तथा नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
- इसमें लगभग 750 स्टॉल्स स्थापित हैं। इसमें देश के 18 राज्यों से 700 से अधिक हस्तशिल्पी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उत्सव में अपने स्टेक होल्डर को विपणन सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- इस बार उत्सव की मुख्य थीम 'विकासशील राजस्थान - उद्यमशील राजस्थान' है। इसे परिलक्षित करते हुए केंद्रीय पंडाल में औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की गई आधारभूत सुविधाओं एवं क्षेत्र के समग्र औद्योगिक विकास का दिग्दर्शन कराने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के मॉडल्स का सुंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान के विकास एवं गांधीवादी विचारधारा प्रदर्शित करने हेतु जीवंत पैनोरमा आकर्षण का केंद्र होगा।
- इस उत्सव का सूत्रपात 33 वर्ष पूर्व जोधपुर सूचना केंद्र में एक लघु औद्योगिक प्रदर्शनी के रूप में हुआ था। इसके अगले वर्ष पुराने स्टेडियम में इसने उद्योग मेले का स्वरूप पाया। वर्ष 1991 में मात्र 80 स्टॉल्स के साथ प्रारंभ यह उत्सव निरंतर व्यापकता पाता गया।
- इस बार उत्सव स्थल पर राजस्थान के अधिकांश ज़िलों के अलावा विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड आदि के लघु-कुटीर औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय का लाभ प्राप्त होगा।

नोट :

सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में राजस्थान देश में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

6 जनवरी, 2023 को राजस्थान के जन अभियोग निराकरण विभाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान 'सुशासन सप्ताह- प्रशासन गाँवों की ओर- 2022' के तहत राजस्थान ने दो श्रेणियों- सेवा प्रदायगी (सर्विस डिलीवरी) एवं जन अभियोग निराकरण में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- जन अभियोग निराकरण विभाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के दौरान चलाए गए 'सुशासन सप्ताह- प्रशासन गाँवों की ओर' अभियान के दौरान संपूर्ण देश में जन अभियोग (Public Grievances)के 53 लाख 80 हज़ार प्रकरण निस्तारित किये गए, जिसमें से राजस्थान ने 23 लाख 36 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- सेवा प्रदायगी (Service Delivery) के पूरे देश में वर्ष 2022 में अभियान के दौरान 310 लाख प्रकरण निस्तारित हुए, जिसमें से राजस्थान ने सेवा प्रदायगी के 149 लाख आवेदन निस्तारित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- उन्होंने बताया कि सेवा प्रदायगी में ज़िला अलवर 16 लाख 45 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर प्रथम स्थान पर जबकि जयपुर 14 लाख 53 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर द्वितीय तथा सीकर ज़िला 12 लाख 92 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर तृतीय स्थान पर रहा।
- इसी प्रकार जन अभियोग निराकरण में ज़िला जयपुर 2लाख 62 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर प्रथम स्थान पर, जोधपुर एक लाख 19 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर द्वितीय और अलवर ज़िला एक लाख 17 हज़ार प्रकरण निस्तारित कर तृतीय स्थान पर रहा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य को अग्रणी बनाने में जन अभियोग निराकरण विभाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग द्वारा प्रत्येक माह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली संभाग स्तरीय समीक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे फील्ड के अधिकारियों में आमजन की परिवेदनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई।
- राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि जन शिकायतों के निवारण के लिये राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 24×7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है तथा मिशन मोड में प्रत्येक माह में त्रिस्तरीय जनसुनवाई ग्राम स्तर, उपखंड स्तर एवं ज़िला स्तर पर की जा रही है।
- निदेशक लोक सेवाएँ एवं संयुक्त शासन सचिव डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की स्थापना के लिये लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी को अधिनियमित करने वाले अग्रणी राज्यों में रहते हुए राजस्थान वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लाने के साथ ही 2012 में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाने वाला प्रथम राज्य है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में आमजन को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 308 सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी के साथ ही त्वरित एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत 624 सेवाओं की प्रदायगी ऑनलाइन की जा रही है, ताकि आमजन को दूरस्थ कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़े।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर

चर्चा में क्यों ?

7 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राज्य के जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का शिलान्यास किया था।
- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनने के बाद यहाँ पर कला-संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी व गैर-सरकारी गतिविधियाँ हो सकेंगी।

नोट :

- यहाँ पर 700 व्यक्तियों की क्षमता का सभागार, 500 क्षमता का कन्वेंशन सेंटर, 170-170 बैठक क्षमता के दो मिनी सभागार, 500 क्षमता का एग्जीबिशन एरिया, 3 कॉन्फ्रेंस हॉल, ई-लाइब्रेरी, 3 लैक्चर हॉल, 2 रेस्टोरेंट, प्रशासनिक सेक्शन, डबल बेसमेंट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी बनेगा, जिसमें जिम की सुविधा भी होगी।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सेंटर का आंतरिक निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर हो रहा है। सभागार की दीवारें जैसलमेरी पैटर्न के अनुरूप होंगी। कन्वेंशन हॉल एवं प्री-फंक्शनल एरिया में सिटी पैलेस जयपुर के आधार पर हॉल एवं हवामहल जयपुर स्टाइल के आधार पर दीवारें दिखेंगी।
- उन्होंने बताया कि मारवाड़ पैटर्न पर मिनी सभागार तैयार किया जा रहा है। जोधपुर के मंडोर उद्यान की पुरातन कला के मेहराब एवं स्मारक अनुरूप कॉन्फ्रेंस हॉल, अत्याधुनिक इंटीरियर पैटर्न के अनुरूप लैक्चर हॉल और रेस्टोरेंट तैयार हो रहा है।

रालसा के वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

9 जनवरी, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति पंकज मित्थल एवं मुख्य संरक्षक, रालसा, न्यायाधिपति एम.एम. श्रीवास्तव द्वारा रालसा के वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्राधिकरण के सदस्य सचिव देनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कैलेंडर में रालसा द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित किये गए 18वीं अखिल भारतीय मीट, विधिक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस व अन्य विशेष दिवस की झलकियों को शामिल किया गया है।
- इसके अलावा कैलेंडर में पोक्सो अधिनियम सेमीनार, रैन बसेरा निरीक्षण, विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजन की गई खेल-कूद प्रतियोगिताएँ तथा विधिक जागरूकता फैलाने व नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने से संबधित अन्य गतिविधियों की झलकियों को भी सम्मिलित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा 07.07.1998 को अस्तित्व में आया।

अठारहवीं राष्ट्रीय जंबूरी का समापन

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2023 को पाली ज़िले के निंबली (रोहठ) में आयोजित अठारहवीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जंबूरी का समापन हुआ। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब राजस्थान के नाम रहा। आयोजन में सम्मिलित हुए राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 4 जनवरी को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जंबूरी में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी पाली जिले के रोहट में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था।
- राष्ट्रीय जंबूरी में भाग ले रहे राज्यों में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिये सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। साथ ही सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिये नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिये नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड राजस्थान ने अपने नाम किये।
- गौरतलब है कि इस पूरे आयोजन के दौरान राजस्थान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं, जिनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े अस्थायी स्टेडियम, यूनिफार्म में सर्वाधिक छात्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण पर ली गई शपथ आदि कई रिकॉर्ड बने।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के जंबूरी के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने राजस्थान की अतिथि देवो भव की परंपरा को सार्थक करते हुए प्रदेश को मिले नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को प्रदान की।
- इस राष्ट्रीय आयोजन में विभिन्न देशों के कुल चार सौ से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से आए 37 हज़ार से ज्यादा स्काउट्स एंड गाइड्स ने हिस्सा लिया।

नोट :

बीकानेर हाउस प्रबधंन समिति और भारत कला मेला के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को राजस्थान के बीकानेर हाउस परिसर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत कला मेला और बीकनेर हाउस प्रबंधन समिति के मध्य राजधानी दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पर पियाली दास गुप्ता, कार्यक्रम निदेशक, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और उमा जैकेब निदेशक बाहरी संबंध एवं आउटरीच (आईएएफ) ने किये।
- बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और भारत कला मेला का यह समझौता ज्ञापन राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से जोड़ेगा जो कि एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- गौरतलब है कि भारत कला मेला के साथ इस समन्वय से बीकानेर हाउस 2 फरवरी से 15 फरवरी तक भारत कला मेला के कार्यक्रमों में सहयोगी ईकाई और साथ भागीदार बनेगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (समन्वय) सह मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने बताया कि भारत कला मेला 2023 के आगामी संस्करणों के लिये कला और सांस्कृतिक गतिविधियाँ को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर हाउस को स्थल भागीदार और यंग कलेक्टर्स प्रोग्राम हब के रूप में स्थापित करने के लिये बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति (बीएचएमएस) भारत कला मेला के साथ सहयोग करेगा।
- भारत कला मेला के साथ यह समन्वय बीकानेर हाउस में क्यूरेटेड इवेंटस पर भविष्य के सहयोग के लिये एक पथप्रदर्शक कार्यक्रम साबित होगा तथा बीएचएमएस और आईएएफ दोनों कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग एवं व्यापक योगदान देंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय कला मेला (आईएएफ) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में आधुनिक एवं समकालीन कला की खोज के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत कला मेला की ओर से ओखला के (एनएससीआई) मैदान में 9 फरवरी से 12 फरवरी, 2023 तक प्रमुख कलाकारों, सहभागियों की मदद से वार्षिक चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज मित्थल ने न्यु हाइकोर्ट बिल्डिंग में राजस्थान के 23 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम का शुभारंभ किया। शेष 13 न्यायक्षेत्रों में सिस्टम की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम राज्य में कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में सक्षम एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रदान कराने तथा उनकी न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
- मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू करने का विचार यूरोप के पब्लिक डिफेंडर सिस्टम के समकक्ष है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के पात्र व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में ढाँचागत सक्षम एवं प्रभावी विधिक सेवाएँ उपलब्ध करवाकर उनकी न्याय तक पहुँच को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को देश में 22 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 365 ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों में प्रारंभ किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत प्रथम फेज में राजस्थान के समस्त 36 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है।

नोट :

विद्युत उपभोक्ताओं के लिये एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू

चर्चा में क्यों ?

12 जनवरी, 2023 को राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य में कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों व अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिये विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि व राजस्व हानि को रोकने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिये 30 जून, 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई है।
- इस योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व विलंब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी और यदि उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 के दौरान जमा कराया जाता है तो विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसंबर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेगें। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया गया है उनके लिये यह योजना उपलब्ध नही होगी और इस योजना के अंतर्गत चोरी व दुरुपयोग के मामले शामिल नही किये जाएंगे।
- योजना के तहत उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक जमा करवाने अथवा संपूर्ण बकाया राशि विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट के साथ 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक जमा करवाने पर प्रावधानानुसार पुन: जोड़ा जा सकेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- भँवर सिंह भाटी ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसंबर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
- योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाई एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
- योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी। ऐसे कृषक जो उसी कुएँ पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएँ पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और यदि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत हैं और कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहें तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना की समाप्ति 31 मार्च, 2023 के उपरांत भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा और चेकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।

नोट :

अंधता नियंत्रण के लिये पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार 'राइट टू साइट विजन' के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता निवारण के लिये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। राज्य में तीन लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1 प्रतिशत थी, जिसे 'राइट टू साइट विजन' पॉलिसी के द्वारा 0.3 प्रतिशत तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
- राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किये जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कॉर्निया को प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के ज़िलों में इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास किये जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को साथ लेकर व्यापक स्तर पर नेत्रदान के लिये मुहीम चलाई जाएगी। नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी, नेत्रदान के लिये कार्यरत काउंसलर्स एवं नेत्र सहायक आदि को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत अंधता नियंत्रण संबंधी जन-जागरुकता और विभिन्न तकनीकी सुधार गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के प्रारूप का किया अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिये 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'के प्रारूप का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- इस योजना से मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। साथ ही युवाओं के शिक्षित होने से परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा तथा समुदाय का सामाजिक उत्थान भी होगा।
- प्रारूप के अनुसार, योजना में 2.50 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले मिरासी (ढाढ़ी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थी पात्र होंगे।
- इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के 2000 विद्यार्थियों को 5000 से 20000 रुपए तक प्रति शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये विभिन्न कार्यों की घोषणा की थी।

नोट :

मुख्यमंत्री ने 'गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना' को दी सहमति

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिये 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'के प्रारूप का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- इस योजना से मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। साथ ही युवाओं के शिक्षित होने से परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा तथा समुदाय का सामाजिक उत्थान भी होगा।
- प्रारूप के अनुसार, योजना में 2.50 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले मिरासी (ढाढ़ी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थी पात्र होंगे।
- इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के 2000 विद्यार्थियों को 5000 से 20000 रुपए तक प्रति शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये विभिन्न कार्यों की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने 'गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना' को दी सहमति

चर्चा में क्यों ?

15 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में 'गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना' को सहमति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिये लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंज़ूरी दी है।
- इस योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिये सक्षम कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्था) उपलब्ध होगी, वहाँ प्राथमिकता से एक-एक करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएँ स्थापित की जाएंगी।
- इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 एवं 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी 10 प्रतिशत राशि वहन करेगी।
- मुख्यमंत्री द्वारा स्थलों के निर्माण एवं संचालन के लिये वर्ष 2022-23 में 60 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023-24 के लिये 1193.40 करोड़ रुपए सहित कुल 1377 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- इस निर्णय से आवारा एवं निराश्रित पशुओं के लिये एक स्थाई आश्रय मिल सकेगा। किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थलों का संचालन किये जाने की घोषणा की गई थी।
- राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में निरंतर निर्णय लिये जा रहे हैं। प्रदेश में संचालित गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशालाएँ खोली जा रही हैं। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध पर अनुदान भी मिल रहा है।

'हर घर पंचायत अभियान' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 जनवरी, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु एक अभिनव पहल करते हुए अलवर ज़िले के गाँव पूनखर से 'हर घर पंचायत अभियान'का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि 'हर घर पंचायत अभियान'के तहत हर ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर, हर घर में पहुँचकर ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा और ग्रामीणों की बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य रही है, जिसके तहत आमजन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- उन्होंने ग्रामीणों को राज्य सरकार की पेंशन, पालनहार, मनरेगा सहित फ्लैगशिप योजनाओं की पंपलेट व प्रचार सामग्री वितरित कर जानकारी दी तथा ग्रामीणों से जागरूक रहकर इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके। इस उद्देश्य के साथ 'हर घर पंचायत अभियान'एवं जनसंवाद कार्यक्रम को अलवर ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया है, जिसके तहत घर-घर दस्तक देकर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनका हाथों-हाथ समाधान किया जाएगा।
- इस तरह घर-घर पहुँचकर समस्याओं का समाधान करने वाला अभियान प्रदेश में पहली बार चलाया गया है, जो अपने आप में एक अनूठा कदम है। इस अभियान से आमजन की घर बैठे ही समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राजस्थान क्रीड़ा परिषद में कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान क्रीड़ा परिषद समिति के अध्यक्ष सतवीर चौधरी तथा युवा मामले एवं खेल विभाग के वित्तीय सलाहकार कोषाध्यक्ष होंगे। जयपुर निवासी मोहम्मद इकबाल एवं भीलवाड़ा के शाहपुरा निवासी अनिल व्यास स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
- आदेश के अनुसार सभी मनोनीत पदाधिकारियों, सदस्यों का मनोनयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 वर्षों अथवा राज्य सरकार द्वारा उनका मनोनयन वापस लेने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगा।

राज्यपाल ने 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का राजभवन में लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) द्वारा इस पुस्तक का भारत भर में उपयोग सुनिश्चित करने के लिये इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
- लोकार्पण के बाद राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के लिये ही नहीं, यह शिक्षकों और अभिभावकों के लिये भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री ने मूलत: परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में लेखन किया है, साथ ही इसमें जीवन प्रबंधन पर भी विशिष्ट जानकारियाँ दी गई हैं।
- इस पुस्तक में विद्यार्थियों की सहायता के लिये योग के कई आसनों के साथ ही परीक्षा को उत्सव, उमंग और उल्लास से देने, परीक्षा पर हँसते हुए जाने और मुस्कराते हुए आने, वर्तमान में रहने, खेलों से जीवन सँवारने आदि पर भी महती सूत्र दिये गए हैं।
- इस पुस्तक में शिक्षकों को पत्र लिखने के साथ ही ज्ञान को स्थायी संपदा बताते हुए इसे जीवन भर सीखने का आह्वान किया गया है।
- एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा असमी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं में इसके अनुदित संस्करण प्रकाशित किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' संवाद प्रयोजन से इस पुस्तक को लिखा था।

नोट :

राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार के मध्य समझौता पत्र करार किया गया जिसके अंतर्गत राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली, जयपुर में की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। केंद्र सरकार की ओर से मनीष वर्मा, निदेशक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, देहरादून एवं राज्य सरकार की ओर से डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता ने हस्ताक्षर किये।
- कंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि एमओयू के पश्चात् अस्थायी रूप से कंपोजिट रीजनल सेंटर का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर के स्थायी संचालन हेतु भूमि केंद्र सरकार को उपलब्ध करवाई जाएगी और चिन्हित भूमि पर भारत सरकार द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर के भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
- इस केंद्र के संचालन से राज्य के दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। दिव्यांगजनों को इस केंद्र से नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवम् उपकरण की सुविधा प्राप्त होगी।
- इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को चिन्हित करना, फिजियोथैरेपी,ऑक्यूपेशनल थेरेपी इत्यादि की सुविधाएँ भी नि:शुल्क प्रदान की जाएगी, साथ ही साथ दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी करवाने में भी इस केंद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 'FITUR-2023' में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 'FITUR-2023' में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया जाएगा।
- पाँच सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के रूप में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, आरटीडीसी के प्रबंध निदेशक विजयपाल सिंह, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक सलीम खान एवं उपनिदेशक नवकिशोर बसवाल ने भाग लिया।
- आरटीडीसी अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में स्पेन सहित अन्य यूरोपीय देशों से पर्यटकों की वर्षभर आवक रहती है। इस फेयर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञों, ट्रेवल एजेंट्स, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स एवं अन्य पर्यटन से जुडी एजेंसी से चर्चा की जाएगी ताकि राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
- उन्होंने कहा कि 'FITUR-2023' राजस्थान की पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने में मददगार होगा।
- आरटीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान की पर्यटन की संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर अवगत करवाने के उद्देश्य से पर्यटन से जुड़ी सभी टूर, ट्रेवल एजेंसियों एवं पर्यटन विशेषज्ञों को 'पधारो म्हारे देश'के माध्यम से राजस्थान आने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

नोट :

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिये राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद और आरोह कंसल्टिंग के बीच करार

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिये राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद और आरोह कंसल्टिंग के बीच द्विपक्षीय करार पर उद्योग भवन में आरईपीसी के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और आरोह कंसल्टिंग की निदेशक अरुंधति मुखर्जी ने हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- आरईपीसी के मुख्य कार्यकारी पी.आर शर्मा ने बताया कि द्विपक्षीय करार के अनुसार आरईपीसी और आरोह समूचे प्रदेश में एमएसएमई के लिये डिजिटलीकरण और निर्यात सुविधा जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाने के लिये पाठ्यक्रम और संकाय प्रदान करने पर सहयोग करने के लिये सहमत हुए हैं।
- आरोह कंसल्टिंग की संस्थापक निदेशक अरुंधति मुखर्जी ने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ाने, विदेशी बाज़ारों में विस्तार करने और एमएनसी के रूप में जाने जाने वाले एमएसएमई टैग को हटाने में मदद करने के लिये संस्था तत्पर रहेगी।
- आरोह कंसल्टिंग के पास अपने बाज़ारों का विस्तार करने और अपनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिये एमएसएमई का समर्थन करने में 7 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
- पी.आर शर्मा ने बताया कि समझौते के एक हिस्से के रूप में, आरोह सभी आकार के एमएसएमई के डिजिटलीकरण के लिये कम लागत वाले समाधान लाने हेतु प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करेगा। यह प्रशिक्षण के लिये एजेंडा भी विकसित करेगा और अगले 2 वर्षों में इसके लिये योग्य और अनुभवी फैकल्टी प्रदान करेगा।
- उन्होंने बताया कि आरोह विभिन्न देशों के खरीदारों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय करने के लिये भारत और विश्व स्तर पर संघों के साथ काम करेगा। राजस्थान में सूक्ष्म उद्यमों द्वारा नए-पुराने आईटी उपकरणों की सुविधा और उनका उपयोग करते हुए उन्हें व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।
- उन्होंने बताया कि इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिये डेटा रहित निर्णय लेने के लिये आवश्यक सभी व्यावसायिक डेटा तक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी। इससे प्रदेश की एमएसएमई इकाईयाँ अपने उत्पादों की मांग और उपलब्धता के आधार पर देश-विदेश में कारोबार को नई दिशा दे सकेगी।

राजकीय महाविद्यालयों में हुआ गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री तथा चूरू ज़िला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला तथा ज़िला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने ज़िले के सरदारशहर मुख्यालय पर राजकीय एस बी डी कॉलेज एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने गांधी दर्शन पर विचार व्यक्त करते हुए बताया कि समय के साथ-साथ गांधी के विचार अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। गांधी ने दुनिया को सत्याग्रह नामक हथियार दिया और साबित किया कि बिना हिंसा के भी जीवन का कोई भी युद्ध लड़ा जाना संभव है।
- उन्होंने बताया कि गांधी साहित्य एक मार्गदर्शक है। जीवन में साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिये। गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सभी को सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिये।

नोट :

- राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ज़िला संयोजक दुलाराम सहारण ने प्रभा खेतान फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि गांधी दर्शन जीवन का पथ प्रेरक है और अशांति और हिंसा के इस माहौल में अहिंसा और शांति का वातावरण स्थापित करने में गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर अत्यंत उपयोगी साबित होंगे।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा भी बेहतर रूप से संचालित होने वाले कॉर्नर में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी क्योंकि गांधी साहित्य की किताबें व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं।

एमओयू साइनिंग सेरेमनी

चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिये 23 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू साइनिंग सेरेमनी में अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, जिससे लगभग 13,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य के विकास के लिये राज्य सरकार निवेशकों के साथ सस्टेनबल पार्टनरशिप बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन हितधारकों के साथ सहयोग करने और किये गए वादों को पूरा करने में मदद कर रहा है।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि इन्वेस्ट समिट के प्रति उद्योग जगत ने उत्साहजनक रुझान प्रदर्शित किया है। यह एमओयू साइनिंग सेरेमनी राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को आगे ले जाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित होगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप पॉलिसी एवं सेक्टर स्पेसिफिक नीतियाँ, जैसे- एनआरआर पॉलिसी 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान स्टार्ट-अप नीति 2022, राजस्थान फिल्म टूरिज़्म प्रमोशन पॉलिसी 2022, राजस्थान टूरिज़्म पॉलिसी 2020, राजस्थान कृषि व्यवसाय नीति 2019 इत्यादि आरंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने दी पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु समिति के गठन की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया जाएगा। समिति का सदस्य सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग तथा समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा।
- प्रस्ताव के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अनेक कारणों से नहीं हो पाने तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में मार्गदर्शन के लिये प्रकरणों का अध्ययन कर सिफारिश करने हेतु पृथक् से समिति का गठन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 12.2022 को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

नोट :

विधानसभा अध्यक्ष ने बनास नदी पर किया एनिकट का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

21 जनवरी, 2023 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने प्रदेश के राजसमंद ज़िले के नाथद्वारा क्षेत्र के नमाना ग्राम में उत्तम सिंचाई व जल प्रबंधन व्यवस्था के लिये लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एनिकट का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने बताया कि एनिकट निर्माण से क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा तथा गाँव के किसानों को सिंचाई के लिये पानी की कमी नहीं आएगी।
- सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि राजस्थान सरकार की योजनाओं ने देश में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में पहचान दिलाई है।
- कार्यक्रम में एनिकट के अलावा जल संसाधन विभाग द्वारा मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य फतेहपुरिया तालाब व अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया गया।
- इसके अलावा नंदसमंद बांध की दाई मुख्य नहर की फुलपुरा माइनर का भी लोकार्पण किया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने हरमाड़ा में किया शहरी जल संवर्द्धन योजना का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने जयपुर शहर के हरमाड़ा एवं बढारणा क्षेत्र को बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराने के लिये शहरी जल संवर्द्धन योजना का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि शहरी जल संवर्द्धन योजना के तहत 1500 किलो लीटर एवं 700 किलो लीटर क्षमता के दो उच्च जलाशय एवं 1800 किलो लीटर व 1400 किलोलीटर क्षमता के दो स्वच्छ जलाशयों के निर्माण के साथ ही 143 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डाली जाएगी।
- इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र की भट्टा बस्ती में पर्याप्त दबाव से पेयजल आपूर्ति के लिये बन रहे 2 हज़ार किलो लीटर क्षमता के उच्च जलाशय एवं 10.6 किलोमीटर डीआई पाइप लाइन बिछाने के कार्यों का भी शिलान्यास किया। इन कार्यों की लागत 8 करोड़ 17 लाख रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि हरमाड़ा-बढारणा को बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये शहरी जल संवर्द्धन योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में शामिल है।
- इस पेयजल योजना का लाभ हरमाड़ा एवं बढारणा क्षेत्र की गायत्री नगर, सुदामापुरी, गंगा विहार, विजय नगर, कृष्णा नगर, श्याम नगर, ओमपुरी, न्यू करणी कॉलोनी, भगवान नगर, गौतम एन्क्लेव आदि कॉलोनियों की करीब 60 हज़ार की आबादी को लाभ मिलेगा।
- इस पेयजल संवर्द्धन योजना से हवामहल विधानसभा क्षेत्र के पाँच वार्डों की पेयजल समस्या का दीर्घकालीन समाधान होगा और साथ ही भट्टा बस्ती के ए, बी, सी एवं डी ब्लॉक, शिवाजी नगर, राजीव नगर, न्यू संजय नगर, बजरंग नगर, शहीद इंद्रा ज्योति नगर, विजय नगर आदि में पर्याप्त दबाव से शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

केंद्रीय कारागार अलवर में 'आशाएँ दा फिलिंग स्टेशन' का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य में कारागार विभाग की बंदियों को रोज़गार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में पेट्रोल पंप 'आशाएँ दा फिलिंग स्टेशन'का शिलान्यास किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि कारागार विभाग की इस पहल से खुली जेल में रहने वाले अच्छे चाल-चलन व आचरण वाले बंदियों को उनकी योग्यतानुसार रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। बंदी व उनके परिवार के लिये ससम्मान जीवनयापन करने के साथ, समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिये यह प्रयास अहम कड़ी साबित होगा।
- इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों द्वारा ही किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग कारागार मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जेल के बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। वहीं खुली जेल में रहने वाले कैदियों को इन नवाचारों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
- केंद्रीय कारागार के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि कारागार विभाग एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. के सहयोग से केंद्रीय कारागार परिसर में 'आशाएँ'संस्था द्वारा यह पेट्रोल पंप संचालित होगा।
- प्रथम चरण में पेट्रोल और डीजल एवं द्वितीय चरण में सीएनजी भी यहाँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। करीब डेढ़ से दो माह में यह पेट्रोल पंप प्रारंभ हो जाएगा।
- प्रदीप लखावत ने बताया कि पेट्रोल पंप के लिये चयनित भूमि पर से हटाए गए वृक्षों की जगह जेल परिसर में कई गुना अधिक वृक्ष लगाए गए हैं, जिनकी देखरेख जेल के बंदियों द्वारा की जाएगी।

राजस्थान टूरिज़्म पोलो कप टूर्नामेंट

चर्चा में क्यों ?

16 से 22 जनवरी, 2023 तक राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब द्वारा जयपुर के रामबाग पोलो क्लब मैदान में राजस्थान टूरिज़्म पोलो कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें फाइनल मैच में बेदला ट्रोजंस ने रजनीगंधा अचीवर्स को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान टूरिज़्म पोलो कप टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह की हैट्रिक की बदौलत बेदला- ट्रोजंस ने रजनीगंधा अचीवर्स को 7-4 से मात दी।
- राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने विजेताओं को राजस्थान टूरिज़्म पोलो कप प्रदान किया।
- पर्यटन निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि राजस्थान टूरिज़्म पोलो कप का आयोजन आने वाले दिनों में प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये महत्त्वपूर्ण आयोजन साबित होगा और इसके ज़रिये प्रदेश का पर्यटन विभाग पोलो टूरिज़्म क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।
- उल्लेखनीय है की 16 से 22 जनवरी तक चले इस टूर्नामेंट में चार टीम बेदला ट्रोजंस पोलो, रजनीगंधा अचीवर्स, कृष्णा पोलो और सामोद पोलो ने भाग लिया। वहीं, टूर्नामेंट में देश-विदेश के खिलाड़ियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

समूचे प्रदेश में एक माह का खान सुरक्षा अभियान शुरू

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को राजस्थान के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि राज्य के माइंस विभाग द्वारा 23 जनवरी से समूचे प्रदेश में खान सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि अभियान के दौरान जोन, वृत्त, खंड, उपखंड अधिकारियों के साथ ही विभाग के सतर्कता अधिकारियों द्वारा खनिज खनन/उत्पादन करने वाले कम से कम 15 खनन पट्टों/30 क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन सुरक्षा नियमों व प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि विभाग के अन्य अधिकारियों को भी कम से कम पाँच खनन लाइसेंसधारियों के यहाँ जाकर निरीक्षण करना होगा।
- एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सुरक्षित खनन कराने आवश्यक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर दिया गया था। इसके लिये विभाग द्वारा 23 जनवरी से 22 फरवरी तक एक माह का अभियान आरंभ किया गया है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (आरएमएमसीआर), खान संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 (एमसीडीआर) और मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 (एमएमआर) के साथ ही माइंस अधिनियम 1952 की विभिन्न धाराओं में सुरक्षित खनन के संबंध में आवश्यक प्रावधान उपलब्ध हैं।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दौरान खनन पटो व क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों के लिये पर्यावरण विभाग द्वारा जारी कंसेट टू ऑपरेट और एनवायरमेंट क्लीयरेंस में निर्देशित प्रावधानों, पर्यावरण व खनिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये जारी सुरक्षा प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में नियमानुसार सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से खनिक श्रमिकों के स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियाँ संचालित करने का प्रावधान है। खान अधिनियम के अनुसार खनिक श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सकीय उपकरण आदि की उपलब्धता होना ज़रूरी है।
- इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, खनन क्षेत्र की सीमांकन, खनन गतिविधियों के सुपरविजन के लिये क्वालीफाईड व्यक्ति को नियोजित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने की स्थिति में खनन गतिविधियों को बंद करवा कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
- एसीएस माइंस ने बताया कि एमसीडीआर के तहत खनन कार्यों के दौरान वैज्ञानिक विधि से खनिज संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियाँ संचालित करने का प्रावधान है। अभियान के दौरान इनकी पालना के साथ ही एबेंडोनेड माइंस के पुनर्भरण एवं माइंस क्लोजर प्लान की पालना का निरीक्षण किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि इसके साथ ही खानों के ओवरबर्डन या वेस्ट आदि निर्धारित स्थान पर रखने और बेक फिलिंग प्रावधानों की पालना भी देखी जाएगी।
- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एमएमआर, 1961 में ओपन कास्ट माइंस की बेंच, हाईट, विड्थ, साइड के स्लोप एंगल, डीप होल ब्लास्टिंग और भारी मशीनरी के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश है ताकि खनन कार्य सुरक्षित व वैज्ञानिक तरीके से हो सके।

अब भिवाड़ी में भी होगी एसीबी चौकी

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अलवर ज़िले में संचालित 2 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चौकियों में से 1 चौकी को भिवाड़ी में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी राजस्थान के अलवर ज़िले का ही एक नगर है, जहाँ एसीबी की चौकी स्थापित होगी।
- वर्तमान में अलवर ज़िले में एसीबी की 2 चौकियाँ संचालित हैं तथा भिवाड़ी में एक भी चौकी स्थापित नहीं है। भिवाड़ी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ राज्य एवं केंद्र सरकार के कई विभागों के कार्यालय स्थित हैं।
- वर्तमान में भिवाड़ी की परिवेदनाओं पर अलवर चौकी ही कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आमजन और शिकायतकर्त्ताओं को चौकी तक पहुँचने में सुविधा होगी।

नोट :

राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार का द्वीप, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नामकरण

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। इस सूची में राजस्थान के परमवीम चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का नाम भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- जोधपुर में एक दिसंबर 1924 को जन्मे शैतान सिंह के पिता हेम सिंह भाटी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। पिता से विरासत में मिली बहादुरी और देश प्रेम के जज्बे के साथ जोधपुर स्टेट फोर्स के इस जांबाज ने एक अगस्त 1949 में कुमाऊँ रेजीमेंट में तैनाती ली। 1962 में शैतान सिंह पदोन्नत होकर मेजर नियुक्त किये गए।
- 18 नवंबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध में लद्दाख की चुशुल घाटी में 13 कुमाऊँ रेजीमेंट के लगभग 120 जवानों की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए मेजर शैतान सिंह ने रेजांगला में मोर्चा सँभाला और अपनी टुकड़ी के साथ खुद के दम पर 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था।
- इनके बारे में बताया जाता है कि मशीनगन को रस्सी से पैरों में बांधकर इस वीर सपूत ने दुश्मन सेना से लोहा लिया। आखिर में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमेशा के लिये अमर हो गए।
- बर्फ से ढके उस क्षेत्र में तीन महीने बाद मेजर शैतान सिंह का शव शिलाखंड के पीछे उसी स्थान पर मिला था, जिसे जोधपुर ले जाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण के लिये सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को सम्मान प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप'रख दिया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर 'शहीद द्वीप'और 'स्वराज द्वीप'कर दिया गया था।
- देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देने के उद्देश्य से इस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है।
- पहले बड़े अज्ञात द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर, दूसरे बड़े अज्ञात द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है और इसी तरह अन्य द्वीपों का नाम रखा गया है।
- इन द्वीपों का नाम जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा वे हैं - मेजर सोमनाथ शर्मा; सूबेदार और मानद कैप्टेन (तत्कालीन लांस नायक) करम सिंह, एम.एम; सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे; नायक जदुनाथ सिंह; कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह; कैप्टन जीएस सलारिया; लेफ्टिनेंट कर्नल (तत्कालीन मेजर) धन सिंह थापा; सूबेदार जोगिंदर सिंह; मेजर शैतान सिंह; सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद; लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर; लांस नायक अल्बर्ट एक्का; मेजर होशियार सिंह; सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल; फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों; मेजर रामास्वामी परमेश्वरन; नायब सूबेदार बाना सिंह; कैप्टेन विक्रम बत्रा; लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे; सूबेदार मेजर (तत्कालीन राइफलमैन) संजय कुमार; और सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त (मानद कैप्टेन) ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।

राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल हुई 25 डिजिटल इंटरसेप्टर

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सड़क सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत पुलिस बेड़े में 25 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात्रि में भी गति मापने एवं वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम हैं। ये वाहन सड़क सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में कारगर साबित होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान पुलिस को इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रयासरत है। पुलिस एवं संबंधित विभागों को अत्याधुनिक संसाधनों व जागरूकता अभियानों के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ दी जा रही हैं।
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी. के. सिंह ने बताया कि ये इंटरसेप्टर कॉन्टेक्टलैस एवं कैशलैस इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करेंगी। यह उच्च गुणवत्ता वाले हाई डेफिनेशन कैमरा सहित एक किलोमीटर दूरी से वाहनों की गति मापने की क्षमता की स्पीड लेजर गन से लैस है। ये इंटरसेप्टर दिन में 250 मीटर तथा रात में 100 मीटर की दूरी से तेज गति वाले वाहनों के नंबर प्लेट पहचान कर सकेंगी।
- इसके अलावा फोटो-वीडियो लेकर एआई तकनीक से NIC के ITMS सुविधा से ई-चालान जारी करने में भी सक्षम है।
- डिजिटल इंटरसेप्टर में लेजर ट्रैक गति कैमरा के अतिरिक्त 360 डिग्री का कैमरा रिकॉर्डर, श्वास से एल्कोहल की मात्रा मापने की डिवाइस, टिंट मीटर, एलईडी साइनेज, एलईडी लाइटबार, उच्च क्षमता का साइरन तथा पीए सिस्टम उपलब्ध है। इनमें प्राथमिक बचाव और चिकित्सा किट भी उपलब्ध है।
- इनमें 4 इंटरसेप्टर यातायात आयुक्तालय जयपुर, 2-2 उदयपुर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, भीलवाड़ा, 1-1 नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, पाली, अलवर, झुंझुनू,जोधपुर ग्रामीण, झालावाड़, सिरोही और कोटा शहर को दी गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज गति एवं नशे में वाहन चलाना शामिल है। राज्य सरकार ने इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए हैं।

कैंपा की संचालन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित शासन सचिवालय में वन विभाग की कम्पंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी अर्थात कैंपा (राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) की संचालन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- समीक्षा बैठक में कैंपा के वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा करने के साथ ही वर्ष 2023-24 हेतु 298.57 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
- इस वार्षिक कार्य योजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने की पश्चात् इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 249.19 करोड़ रुपए की राशि से 49.38 करोड़ रुपए अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि कम्पंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड के नियमों के तहत जारी राशि का उपयोग वन तथा वन्य जीव प्रबंधन एवं इनसे संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण में किया जाता है। इससे वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण होता है।

प्रदेश के आठ रचनाधर्मियों को मिलेगा अमृत सम्मान

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण की अध्यक्षता में हुई अमृत सम्मान समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक उम्र के नौ रचनाधर्मियों को राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान प्रदान करेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अकादमी सचिव डॉ. बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि समिति ने प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए और संचालिका संस्तुति के अनुरूप प्रांत के आठ साहित्य सेवियों का चयन अमृत सम्मान के लिये किया है।
- उन्होंने बताया कि जयपुर के डॉ. सुलोचना रांगेय राघव, पुष्पा शरद देवड़ा, डॉ. कल्याण प्रसाद वर्मा, झालावाड़ के ग्यारसीलाल सेन, बीकानेर के लक्ष्मीनारायण रंगा, सरल विशारद, चूरू के शिव कुमार शर्मा मधुप तथा बाँसवाड़ा की भारती भावसार का चयन वर्ष 2022-23 के अमृत सम्मान हेतु किया गया है।
- ये अमृत सम्मान 28 जनवरी को अकादमी स्थापना दिवस समारोह में अकादमी सभागार, उदयपुर में आयोज्य समारोह में प्रदान किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषा, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, साक्षरता, पत्रकारिता आदि की सेवा करने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के साहित्यकार जिनको इससे पहले अकादमी का कोई भी सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 31 हज़ार रुपए की राशि का यह अमृत सम्मान प्रदान किया जाता है।

प्रदेश की चार विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों 'पद्म पुरस्कारों'की घोषणा की गई। इनमें राजस्थान के चार विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023 के लिये राष्ट्रपति ने तीन द्वय मामलों (एक द्वय मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंज़ूरी दी है।
- सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
- पद्म पुरस्कार के लिये चयनित राजस्थान के चार विभूतियों में मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह और अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन (संयुक्त रूप से) शामिल हैं।
- डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्त्ता मूलचंद लोढ़ा और जयपुर के लापोड़िया गाँव के लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये जबकि हुसैन बंधु उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये पद्म श्री अवार्ड हेतु चुना गया है।
- गजल और कव्वाली गायकी के लिये मशहूर जयपुर के हुसैन बंधुओं को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।
- गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
- यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।
- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म भूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म श्री'से सम्मानित किया जाता है।
- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाते हैं।

नोट :

भगवान श्री देवनारायण जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित

चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य में आमजन की आस्था और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ही भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित करने का यह निर्णय लिया गया है।
- विदित है कि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत तथा खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखकर भगवान श्री देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग की थी।
- उल्लेखनीय है कि भगवान श्री देवनारायण की एक गोरक्षक, असहाय लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले लोक देवता एवं पराक्रमी योद्धा के रूप में आराधना की जाती है। राजस्थान एवं अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में विभिन्न समाज के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री देवनारायण की पूजा की जाती है।
- गौरतलब है कि इस वर्ष भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती 28 जनवरी को मनाई जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2023 को राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने जोधपुर में हुई राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद की बैठक में बताया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास को विश्वपटल पर नई ऊँचाइयाँ देने के उद्देश्य से आगामी 20 से 22 मार्च, 2023 तक जोधपुर के ईपीसीएच सेंटर बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बैठक में बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में जोधपुर से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद फर्नीचर के अलावा कृषि एवं विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण उद्योगों, इंजीनियरिंग उत्पाद, स्टील आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि इसके लिये यूरोप, अमेरिका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के भारतीय दूतावास एवं उच्चायुक्तों के माध्यम से विदेशी क्रेताओं से संपर्क कर इस आयोजन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाएगा। इसमें हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद एवं प्रमुख निर्यातक तथा निर्यातक संगठन भी वांछित सहयोग करेंगे।
- राजीव अरोड़ा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस व्यापार मेले के सफल क्रियान्वयन के लिये विभिन्न उद्यमियों एवं निर्यातकों से सुझाव आमंत्रित कर उन पर मुख्य रूप से अमल किया जाएगा। स्थानीय निर्यातक एवं गैर-निर्यातक उद्यमी इस आयोजन को सफल बनाने के लिये हरसंभव भागीदारी का निर्वाह करेंगे।
- उन्होंने बताया कि एक्सपो से विशेषरूप से संभाग के उन कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिन्हें गाँव-गाँव में काम करके अपने उत्पादों को बेचने के लिये दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों में जाना पड़ता है। इस आयोजन के माध्यम से अधिक-से-अधिक खरीदारों तक उत्पाद पहुंचेंगे तथा स्थानीय उत्पादों के प्रति इनका आकर्षण बढ़ेगा।
- बैठक में बताया गया कि मेला अवधि में जोधपुर शहर में सड़कों के विशेष रख-रखाव व सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस आयोजन में सहयोग के लिये आयोजक संस्थाओं तथा उद्यमियों द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।

नोट :

पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद की संयुक्त बैठक

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल एवं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की शासी परिषद और कार्यकारी परिषद की संयुक्त बैठक में कलाकारों को वर्षों से दिये जा रहे डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार के मानदेय में समय के अनुरूप वृद्धि करने के निर्देश देते हुए इस संबंध में मौके पर ही प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल की मंजूरी के बाद पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिये जाने वाले कोमल कोठारी पुरस्कार की ढाई लाख रुपए की राशि एक-से-अधिक लोगों को दिये जाने पर अब बाँटकर नहीं दी जाएगी। यदि दो कलाकारों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा तो दोनों को ढाई-ढाई लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी।
- इस बैठक में केंद्र के सदस्य राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एवं केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव से शाषी निकाय और कार्यकारी निकाय के सदस्य सम्मिलित हुए।
- इस अवसर पर केंद्र द्वारा 2023 का फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ-ईस्ट ओक्टेव कार्यक्रम गोवा में किये जाने की भी घोषणा की। नॉर्थ-ईस्ट के कलाकारों की कला प्रोत्साहन का यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- राज्यपाल ने बैठक में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत पारंपरिक और लुप्त होती आदिवासी कलाओं के संरक्षण, प्रलेखन और विभिन्न कला रूपों के अधिकाधिक प्रसार के लिये गंभीर होकर कार्य करने के भी निर्देश दिये।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने केंद्र के तहत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली से जुड़ी लोक, पारंपरिक और आदिवासी कलारूपों के संरक्षण, कलाकारों की परस्पर आदान-प्रदान गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान के जाने-माने कला मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉ. कोमल कोठारी की स्मृति में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर द्वारा 'डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार' प्रदान किया जाता है।
- गौरतलब है कि डॉ. कोमल कोठारी को 'कोमल दा' के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लोक कलाओं के संरक्षण के लिये अहम कार्य किये। इन्होंने राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत और वाद्यों के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज आदि के लिये बोरूंदा में रूपायन संस्था की स्थापना की थी।

प्रदेश में अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क्स की स्थापना हेतु टी.एच.डी.सी.एल. एवं आर.आर.ई.सी.एल. के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता का जे.वी. एग्रीमेंट निष्पादित

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को भारत सरकार की मिनीरत्न ए-श्रेणी की कंपनी टी.एच.डी.सी. लिमिटेड तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य जयपुर में जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट निष्पादित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आशुतोष ए.टी. पेडणेकर तथा प्रबंध निदेशक अनिल ढाका की उपस्थिति में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के तकनीकी निदेशक डी.के. शर्मा तथा टी.एच.डी.सी. के चीफ जनरल मैनेजर (सोलर) एस.एस. पवार द्वारा उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- टी.एच.डी.सी. एवं आर.आर.ई.सी. की जॉइंट वेंचर कंपनी में 74:26 प्रतिशत हिस्से की क्रमशः भागीदारी होगी।
- इस अवसर पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि इस जॉइंट वेंचर कंपनी द्वारा प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएंगी, जिससे सस्ती अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति होगी।

नोट :

- इस अवसर पर पेडणेकर द्वारा टी.एच.डी.सी. अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर और पंप स्टोरेज हाईड्रो प्लांट को भी राजस्थान में विकसित कराए जाने के लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया गया।
- आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि प्रदेश में स्थापित होने वाले इस अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क्स की स्थापना प्रदेश में केंद्र सरकार के उपक्रम के साथ अक्षय ऊर्जा के विकास की इस तरह की एक अनूठी पहल साबित होगी।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका ने बताया कि प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क्स की स्थापना से राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के कार्य-कलापों के दायरे का विकास होगा।
- टी.एच.डी.सी. के सी.जी.एम. (सोलर) एस.एस. पवार ने बताया कि इस अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क्स की स्थापना पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का विकास होगा। प्रथम चरण में वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पॉर्क्स का विकास किया जाएगा।

पशु कल्याण पखवाड़े के अंतिम दिन सर्वोदय दिवस का हुआ आयोजन

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को महात्मा गांधी के शहीद दिवस को राजस्थान पशुपालन विभाग एवं जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश में सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के विशेषाधिकारी डॉ. लाल सिंह ने बताया कि बोर्ड द्वारा संपूर्ण वर्ष में जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में पशु कल्याण की भावना को जागृत किया जाएगा।
- विदित है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सर्वोदय दिवस के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है व इस दिन संपूर्ण राज्य में पशु-पक्षियों के वध को निषेध रखना विभिन्न विभागों की सहायता से सुनिश्चित किया जाता है।
- डॉ. लाल सिंह ने बताया कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने जीवन को अहिंसा एवं सर्व कल्याण के लिये समर्पित किया था, वैसे ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिये आवश्यक है कि 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत का पालन किया जाए।
- जयपुर स्थित मानसरोवर के एक निजी विद्यालय में पशु कल्याण पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में मौजूद स्कूली बच्चों ने मानव द्वारा पशुओं को दी जाने वाली यातनाओं से पशुओं को होने वाले दर्द को नाटक के माध्यम से जीवंत किया।
- बच्चों ने दर्शाया कि किस प्रकार मानव अपनी ज़रूरत को प्राथमिकता देते हुए पशुओं के साथ अत्याचार को अंजाम देते हैं। इस मौके पर बच्चों ने पशुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने का संदेश देते हुए पोस्टर एवं स्लोगन को भी दर्शाया। वहीं, कुछ छात्र-छात्राओं ने स्वरचित कविताओं के माध्यम से पशुओं के प्रति दयाभाव रखने एवं पशु कल्याण को प्रेरित करने का संदेश दिया।
- इस अवसर पर मौजूद जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पशु चिकित्सक डॉ. यशपाल द्वारा पोस्टर, बैनर, कविता वाचन एवं नाट्य मंचन करने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रतीक चिह्न एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

नोट :